[2025] 6 एस.सी.आर. 582 : 2025 आईएनएससी 738

रामजी प्रसाद जयसवाल उर्फ़ रामजी प्रसाद जयसवाल एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

(2025 की आपराधिक अपील सं. 490)

20 मई 2025

[अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयां,* न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या मामले के तथ्यों में द.प्र.स की धारा 313 का उल्लंघन हुआ था, जिससे अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ और उनके विरुद्ध मुकदमे को नुकसान पहुंचा।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 313 – दंड संहिता, 1860 – धारा 420, 468, 471, 120बी – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 – धारा 5(2), 5(1)(डी) – अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी के तहत दोषी ठहराया गया, जो धारा 5(2), 5(1)(डी) पीसी अधिनियम के साथ है, और तदनुसार सजा सुनाई गई – अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उनके खिलाफ दर्ज की गई अपराधजनक परिस्थितियों को द.प्र.स की धारा 313 के तहत उनकी जांच में उनके सामने नहीं रखा गया – क्या मुकदमा दूषित हो गया:

अभिनिर्धारित किया: हां – अपीलकर्ताओं से चार समान प्रश्न यांत्रिक तरीके से पूछे गए थे, बिना उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर लाई गई विशिष्ट सामग्री के बारे में बताए – ये प्रश्न विशिष्ट अभियोजन साक्ष्य को प्रतिबिंबित नहीं करते थे जो अपीलकर्ताओं के संबंध में रिकॉर्ड पर आए थे – चूंकि, सभी दोषपूर्ण साक्ष्य अपीलकर्ताओं के ध्यान में नहीं रखे गए थे, इसलिए धारा 313, द.प्र.स के साथ-साथ ऑडी अल्टरम पार्टम के

सिद्धांत का उल्लंघन हुआ, जिससे अपीलकर्ताओं को अपना मामला आगे बढ़ाने में गंभीर पूर्वाग्रह हुआ – अंततः, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए अदालत ने ऐसे साक्ष्य पर भरोसा किया – ऐसी चूक जो एक गंभीर अनियमितता है, ने मुकदमे को पूरी तरह से खराब कर दिया – धारा 313, द.प्र.स के तहत उनके बयानों की रिकॉर्डिंग में ऐसी चूक के कारण अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते समय अपीलकर्ताओं के प्रतिकूल सबूतों पर भरोसा किया था संख्या 3 को किशोर होने के आधार पर रद्द किया जाता है – किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000। [पैरा 28, 36-39]

न्याय दृष्टान्त

शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य **[1974] 1 एससीआर 489: (1973) 2 एससीसी 793**; *धरणीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **[2010] 8 एससीआर 173: (2010) 7 एससीसी 759**; *राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बट्या बनाम राजस्थान राज्य* **[2013] 8 एससीआर 599: (2013) 5 एससीसी 722**; *राज कुमार उर्फ सुमन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)* **[2023] 5 एससीआर 754: (2023) 17 एससीसी 95**; *अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **[2024] 12 एससीआर 335: (2025) 2 एससीसी 381 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000।

मुख्य शब्दों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 का उल्लंघन; दोषारोपण करने वाली परिस्थितियां; दोषारोपण करने वाले साक्ष्य का संज्ञान नहीं लिया गया; समान प्रश्न पूछे गए; यांत्रिक तरीके से; चूक; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग में चूक;

अनियमितता; मुकदमा दूषित; ऑडी अल्टेरम पार्टेम का सिद्धांत; संदेह का लाभ; किशोरता की याचिका; अपराध करने की तारीख को किशोर; उपचार योग्य सामग्री दोष।

प्रकरण से उत्पन्न

2006 के आपराधिक अपील (एस.जे.) सं. 418 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता:

सुश्री मुक्ता गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुदित जैन, सुश्री सम्प्रिका घोषाल, नित्या गुप्ता, सुश्री महिमा मल्होत्रा, आयुष गोस्वामी, सैफुल हक, आदित्य समद्दर।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता:

विक्रमजीत बनर्जी, ए.एस.जी., संतोष कुमार, सुश्री भारती त्यागी, प्रणीत प्रणव, मृगांक पाठक, प्रशांत रावत, त्रिंग चामवीबो जेलियांग, अभिषेक सिंह, मुकेश कुमार मारोरिया।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

उज्जवल भुइयां, न्यायमूर्ति

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 418/2006 में दिनांकित 24.11.2011 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है। उपरोक्त निर्णय और दिनांक 24.11.2011 के आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 430/2006 (शिव नारायण बंसल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य) और आपराधिक

अपील (एसजे) संख्या 418/2006 (रामजी प्रसाद जायसवाल उर्फ रामजी प्रसाद जायसवाल एवं दो अन्य बनाम बिहार राज्य) को खारिज कर दिया।

2. इस अपील में, हम 2006 की आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 418 के संबंध में उच्च न्यायालय के दिनांक 24.11.2011 के निर्णय से चिंतित हैं। इस मामले में तीन अपीलार्थी हैंः

1. रामजी प्रसाद जैसवाल उर्फ रामजी प्रसाद जैसवाल,

2. अशोक कुमार जयस्वाल और

3. बाल मुकुंद जयसवाल।

3. यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं के साथ 2006 की आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 430 के अपीलकर्ताओं पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) और 5(1)(डी) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 (भ.द.स) की धारा 420, 440, 468, 471 और 120 बी के तहत कथित रूप से अपराध करने के लिए विशेष मामला संख्या 52/1983 में विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी.आई.), दक्षिण बिहार, पटना (इसके बाद 'सी.बी.आई. अदालत') की अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया था।

3.1 दिनांक 29.05.2006 के निर्णय और आदेश द्वारा, दोनों आपराधिक अपीलों में अपीलार्थियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) और 5 (1) (डी) के साथ पठित भ.द.स की धारा 420, 468, 471 और 120बी के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया था। तदनुसार, दोनों अपीलों में अपीलार्थियों को भ.द.स की धारा 420 के तहत तीन साल के लिए कठोर कारावास सहने और चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी देने का निर्देश दिया गया था। उन्हें भ.द.स की धारा 468 के तहत तीन साल के लिए कठोर

कारावास भुगतने के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, प्रत्येक अपीलकर्ता को धारा 471 के साथ धारा 468, 420 और 120बी भ.द.स के तहत क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया। एक वर्ष के कारावास की मूल सजा में पी.सी. अधिनियम की धारा 5(1)(डी) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत अपराध के लिए प्रत्येक अपीलार्थी को दी गई सजा शामिल थी। यह निर्देश दिया गया था कि लगाई गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

4. अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित, सभी दोषियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष दो आपराधिक अपीलें दायर कीं, जो 2006 की आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 418 और 430 थीं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बाद, 2006 की आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 430 में दूसरे अपीलार्थी चेतारू सिंह का निधन हो गया। इसलिए, *उनकी* अपील निरस्त कर दी गई। उक्त अपील शेष एकमात्र अपीलार्थी शिव नारायण बंसल के खिलाफ आगे बढ़ी।

4.1 उच्च न्यायालय दिनांकित 24.11.2011 के सामान्य निर्णय और आदेश के *माध्यम से* इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थियों को उचित रूप से दोषी ठहराया गया था और सही सजा दी गई थी। तदनुसार, दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2006 की आपराधिक अपील (एस.जे.) संख्या 418 में अपीलकर्ताः (1) रामजी प्रसाद जैसवाल उर्फ रामजी प्रसाद जैसवाल (2) अशोक कुमार जैसवाल और (3) बाल मुकुंद जैसवाल ने 2012 की संबंधित एसएलपी (आपराधिक) संख्या 2629 दायर की।

6. दिनांक 26.03.2012 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने देरी को माफ करने के बाद केवल सजा के प्रश्न पर अपीलार्थी संख्या 1 और 2 को नोटिस जारी किया। अपीलार्थी सं. 3 के संबंध में, सजा के प्रश्न पर और अपराध करने की तारीख पर उसके किशोर होने के प्रश्न पर भी नोटिस जारी किया गया था।

7. 21.09.2012 पर, इस न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 3 द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका पर विचार किया। मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 3 का जन्म 24.12.1965 पर हुआ था, जिसका अर्थ होगा कि वह दिसंबर 1982 में लगभग 17 वर्ष का था जब कथित रूप से उसके द्वारा अपराध किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने निर्देश दिए कि सी.बी.आई. द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया प्रमाण पत्र वास्तविक पाया गया। इसलिए, इस न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7ए के अनुसार जांच करने, अपीलकर्ता संख्या 3 की किशोरता के प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज करने और उसके बाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने तीनों अपीलार्थियों को जमानत पर बढ़ा दिया और अपीलार्थियों पर लगाई गई शेष सजा को भी निलंबित कर दिया। 21.09.2012 दिनांकित आदेश इस प्रकार हैः

> याचिकाकर्ता संख्या 3 ने आपराधिक शिकायत एम.पी. संख्या 11269/2012 दायर की है, जिसमें अन्य बातों के *साथ-साथ* यह भी बताया गया है कि अपराध की तिथि पर वह किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत किशोर था। उन्होंने उस दावे के समर्थन में दो दस्तावेजों पर भरोसा किया है, जिनमें से एक बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र है। उस प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 3 का जन्म 24.12.1965 पर हुआ था, जिसका अर्थ है कि वह दिसंबर, 1982 में

लगभग 17 वर्ष का था, जब कथित रूप से उसके द्वारा अपराध किया गया था। 17.08.2012 पर, जब यह विशेष अनुमति याचिका हमारे सामने आदेश के लिए आई, तो हमने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एच. पी. रावल को याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए प्रमाण पत्र की वास्तविकता के बारे में निर्देश लेने का निर्देश दिया था। प्रत्यर्थी सी.बी.आई. के विद्वान वकील श्री राजीव नंदा ने आज निर्देश देते हुए कहा कि सी.बी.आई., पटना द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन में जिस प्रमाण पत्र पर भरोसा किया गया है, वह वास्तविक पाया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता संख्या 3 की किशोरता के संबंध में अधिनियम की धारा 7ए के तहत जांच करने का मामला बनाया गया है। तदनुसार हम विशेष न्यायाधीश को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 की धारा 7ए के संदर्भ में जांच करने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आवश्यक दस्तावेज बुलाने, याचिकाकर्ता संख्या 3 की किशोरता के सवाल के संबंध में यदि कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दर्ज करने, प्रश्न पर एक निष्कर्ष दर्ज करने और इस अदालत को शीघ्रता से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं, लेकिन उक्त अदालत द्वारा इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के बाद नहीं।

याचिकाकर्ता नंबर 3 के विद्वान वकील श्री नागेंद्र राय प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता संख्या 3 को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा तथा अपने दावे के समर्थन में उसके द्वारा भरोसा किए गए मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। श्री राय ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता नंबर 1, रामजी प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित लगभग 72 वर्ष के हैं और पहले ही सात साल की जेल से गुजर चुके हैं। इसी

तरह याचिकाकर्ता नंबर 2, अशोक कुमार जायसवाल को कुल तीन साल के कारावास में से सात महीने का कारावास हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से ठगी गई कुल 13,29,266 रुपये की राशि में से, अभियोजन पक्ष के अनुसार भी, इस अपील में याचिकाकर्ताओं द्वारा एक पैसा भी प्राप्त या गबन नहीं किया गया है। कहा जाता है कि संबंधित अपील में अपीलार्थी शिव नारायण बंशल को 57,000/- प्राप्त हुए हैं, जबकि शेष राशि एक अन्य आरोपी व्यक्ति द्वारा ले ली गई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने आग्रह किया कि परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। *प्रथम दृष्टया* हम उस विवाद में योग्यता पाते हैं। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि रामजी जयसवाल, अशोक कुमार और बाल मुकुंद विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभूतियों के साथ 20,000/- के अपने जमानत बांड पर जमानत पर रिहा होंगे। उक्त याचिकाकर्ताओं को दी गई सजा का शेष हिस्सा उस शर्त पर निलंबित रहेगा।

विचारण न्यायालय से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए गैर-विविध दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए सी.बी.आई., पटना को भेजी जाएगी।

8. दिनांकित 05.01.2015 आदेश इंगित करता है कि विचारण न्यायालय से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

9. अंत में, मामले की सुनवाई 29.01.2005 पर हुई, जिस तारीख को अनुमति प्रदान कर दी गई थी।

10. प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में नोट किया जा सकता है।

11. यह मामला सितंबर, 1982 से दिसंबर, 1982 के बीच की अवधि से संबंधित है। उस समय मृतक आरोपी अजय कुमार श्रीवास्तव भारतीय स्टेट बैंक, कृषि बाजार यार्ड शाखा, मोहनिया (संक्षेप में इसके बाद 'एस. बी.आई.') के शाखा प्रबंधक थे। आरोप यह था कि अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मृतक अपीलकर्ता चेथारू सिंह (मेसर्स बिष्णुजी भंडार के मालिक) और अपीलकर्ता शिव नारायण बंसल (मेसर्स बंसल स्टोर्स, मोहनिया के मालिक) के साथ तीन वर्तमान अपीलकर्ताओं यानी रामजी प्रसाद जायसवाल उर्फ रामजी प्रसाद जायसवाल और उनके दो बेटों बाल मुकुंद जायसवाल और अशोक कुमार जायसवाल के साथ साजिश रची और इस तरह धोखाधड़ी और बेईमानी से चेथारू सिंह को 71,456.00 रुपये और शिव नारायण बंसल को 12,57,810.00 रुपये का भुगतान प्राप्त किया, कुछ बिलों के खिलाफ, जो वर्तमान तीन अपीलकर्ताओं द्वारा जारी किए गए नकली परिवहन रसीदों के साथ थे, कथित तौर पर मेसर्स रोहतास कैरियर की ओर से, विभिन्न माल प्राप्तकर्ताओं के अनाज की खेप दिखाते हुए। इस प्रक्रिया में, एस.बी.आई. को मूल राशि के रूप में रुपये 13,29,266.00 का नुकसान हुआ।

12. मेसर्स बिष्णुजी भंडार और मेसर्स बंसल स्टोर्स के चालू खाते एस.बी.आई. में थे। मेसर्स रोहतास कैरियर्स को परिवहन एजेंसी के रूप में दिखाया गया था जिसे वर्तमान तीन अपीलार्थियों द्वारा चलाया जा रहा था। आरोप था कि सभी नोट नकली थे। अभियुक्तों द्वारा और उनके बीच आपराधिक साजिश रचकर, उन्होंने उपरोक्त भुगतान अवैध रूप से और धोखाधड़ी से प्राप्त किया था।

13. जहाँ तक मेसर्स रोहतास कैरियर्स और वर्तमान तीन अपीलार्थियों का संबंध है, आरोप यह था कि मेसर्स रोहतास कैरियर्स का न तो अपना वाहन था और न ही मोहनिया में कोई गोदाम या व्यावसायिक परिसर या शाखा या कार्यालय था। वास्तव में उक्त क्षेत्र में इसका कोई व्यवसाय नहीं था। वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा जारी माल नोट नकली

थे। इसलिए, वे उस आपराधिक साजिश का भी हिस्सा थे जिसके तहत एस.बी.आई. को रुपये 13,29,266.00 का गलत नुकसान हुआ था।

14. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने सत्ताईस गवाहों से पूछताछ की और बड़ी संख्या में दस्तावेजों का प्रदर्शन किया। प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, दायर की गई दो आपराधिक अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और दिनांक 24.11.2011 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

15. इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलें दर्ज करने के लिए आगे बढ़ें, प्रासंगिक तिथियों को उजागर करना उचित होगाः

1. सी.बी.आई. द्वारा 23.06.1983 पर दो प्राथमिकियां दर्ज की गईं जिनमें अपीलकर्ताओं और अन्य को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
2. सी.बी.आई. ने 31.12.1984 पर आरोप पत्र दायर किया।
3. विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. द्वारा 02.09.1986 पर आरोप तय किए गए थे।
4. इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ।
5. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के समापन पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (द.प्र.स) की धारा 313 के तहत 04.01.2006 पर अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए गए।
6. विचारण न्यायालय ने 29.05.2006 को अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

7. उच्च न्यायालय ने 24.11.2011 के निर्णय और आदेश द्वारा दोनों आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया।

16. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि अनुमति दी जा रही है, इसलिए सभी कानूनी विवाद अब अपीलार्थी के लिए खुले हैं।

16.1 धारा 313 द.प्र.स के तहत अपीलार्थियों के बयानों का उल्लेख करते हुए, वे प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें सबसे यांत्रिक तरीके से दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में अपीलार्थियों के खिलाफ जो दोषपूर्ण परिस्थितियां दर्ज की गई थीं, उन्हें द.प्र.स की धारा 313 के तहत जांच के दौरान उनके सामने नहीं रखा गया था। केवल चार सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। वह प्रस्तुत करती है कि इस तरह की अनियमितता के कारण, अपीलार्थियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ था।

16.2 इस मुद्दे को हल करने में विचारण न्यायालयों की विफलता के कारण, अपीलार्थियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ। किसी भी मामले में, चूंकि लगभग दो दशकों की काफी अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थियों के बयान दर्ज करने के चरण से सुनवाई की कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए विचारण न्यायालय में वापस जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए, केवल इसी आधार पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया जा सकता है।

16.3 अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का एक अन्य निवेदन यह है कि अपीलार्थी संख्या 3 बाल मुकुंद जयसवाल की आयु सितंबर, 1982 से दिसंबर, 1982 की अवधि के दौरान 18 वर्ष से कम थी, यानी उस अवधि के दौरान

जब अपराध और आरोप पत्र संबंधित था। इसलिए, अपराध करने की तारीख को वह एक किशोर था। यद्यपि यह आधार विचारण न्यायालयों के समक्ष नहीं लिया गया था, वह प्रस्तुत करती है कि यह तय कानून है कि किसी भी स्तर पर किसी अभियुक्त/दोषी की किशोरता की याचिका ली जा सकती है।

16.4 इसके बाद विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपीलार्थी संख्या 3 के मैट्रिक प्रमाण पत्र का उल्लेख किया है जिसमें उनकी जन्म तिथि 24.12.1965 दिखाई गई है जिसका अर्थ यह होगा कि दिसंबर, 1982 में उनकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। इसके बाद, उन्होंने इस न्यायालय के दिनांकित 21.09.2012 के आदेश के साथ-साथ किशोरता के सवाल पर विशेष न्यायाधीश के निष्कर्ष का उल्लेख किया है।

16.5 अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी अपीलार्थी बरी होने के पात्र हैं। सबसे पहले, धारा 313 द.प्र.स की आवश्यकताओं का पालन करने में अदालत की विफलता के लिए. अपीलार्थियों के लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करना। दूसरा, जहाँ तक अपीलार्थी संख्या 3 का संबंध है, वह अपराध करने की तारीख को एक किशोर होने के कारण, इसलिए, उसे आरोपित दोषसिद्धि और सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

17. *इसके विपरीत*, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक अपीलार्थी संख्या 1 और 2 का संबंध है, अपराध करने में उनकी भागीदारी पूरी तरह से स्थापित हो गई है। विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर सामग्री के आधार पर उन्हें सही तरीके से दोषी ठहराया था जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में की है।

17.1 वह आगे प्रस्तुत करता है कि अब तक धारा 313 द.प्र.स के कथित उल्लंघन का संबंध है, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी के ध्यान में उस साक्ष्य का सार लाया था जो उक्त अपीलार्थी रिकॉर्ड में आए थे। इसलिए, धारा 313 द.प्र.स की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन किया गया था।

17.2 वह प्रस्तुत करते है कि भले ही हम इस धारणा पर आगे बढ़ते हैं कि धारा 313 का उल्लंघन हुआ है, अपीलार्थी संख्या 1 और 2 को तकनीकीता पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिसे रिकॉर्ड पर साक्ष्य की समग्रता के खिलाफ तौला जाना है। दूसरे शब्दों में, वह प्रस्तुत करते है कि तकनीकी आधार पर, अपीलकर्ताओं को नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्यूंकि अभियोजन पक्ष उनके अपराध को स्थापित करने में सक्षम था।

17.3 इसके अलावा, जहाँ तक अपीलार्थी संख्या 3 का संबंध है, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि अब जब विचारण न्यायालय ने अपराध करने की तारीख को उसे किशोर पाया है, तो यह न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है।

18. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर न्यायालय द्वारा उचित विचार किया गया है।

19. आइए सबसे पहले हम अपीलकर्ता संख्या 3 के किशोर होने के प्रश्न पर विचार करें। यह रिकॉर्ड में आया है कि अपीलार्थी संख्या 3 ने बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था, जिसके अनुसार उनकी जन्म तिथि 24.12.1965 है। इसका मतलब यह होगा कि सितंबर, 1982 से दिसंबर, 1982 की अवधि के दौरान उनकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, जब कथित रूप से उनके द्वारा यह अपराध किया गया था। न्यायालय में, सी.बी.आई. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान

वकील ने निर्देशों पर प्रस्तुत किया कि सी.बी.आई. द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 3 द्वारा भरोसा किया गया प्रमाण पत्र वास्तविक पाया गया। इसके बाद, इस न्यायालय ने पहले से ही ऊपर उल्लिखित 21.09.2012 के आदेश के माध्यम से विद्वान विशेष न्यायाधीश को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, 'जेजे अधिनियम') की धारा *7* ए के तहत जांच करने का निर्देश दिया। जेजे अधिनियम की धारा *7* ए ने किसी भी अदालत के समक्ष किशोरता का दावा किए जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित किया। धारा *7* ए इस प्रकार हैः

> ***7* ए. किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—** (1) जब भी किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा उठाया जाता है, या न्यायालय की यह राय है की कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, अदालत एक जांच करेगी, ऐसा साक्ष्य लेगी जो आवश्यक हो (लेकिन एक हलफनामा नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके, और एक निष्कर्ष दर्ज करेगी कि क्या वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं, जिसमें उसकी उम्र लगभग हो सकेः
>
> बशर्ते कि किशोरता का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और इस तरह के दावे का निर्धारण इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले ऐसा होना बंद कर चुका हो।

(2) यदि अदालत किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध करने की तारीख को किशोर पाती है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजेगी और अदालत द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, तो उसका कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।

20. इसलिए, धारा 7ए में विचार किया गया था कि जब किशोरता का दावा किया गया था या यदि अदालत की राय थी कि कोई व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर था, तो अदालत को जांच करने के लिए अनिवार्य किया गया था और ऐसे साक्ष्य लेने के बाद जो आवश्यक हो, अनिवार्य रूप से एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता थी कि क्या व्यक्ति किशोर था या बच्चा था या नहीं, तथा यथासंभव उसकी आयु बतायी गयी थी। परंतुक के अनुसार, किशोरता का दावा किसी भी अदालत के समक्ष और किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। यदि इस तरह की जांच में, अदालत ने अपराध करने की तारीख को व्यक्ति को किशोर पाया, तो उसे उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेजना पड़ेगा और अदालत द्वारा दी गई सजा, यदि कोई हो, को कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।

21. जहां अपराध के आरोप में एक किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, तो जेजे अधिनियम की धारा 14 (1) के संदर्भ में, किशोर न्याय बोर्ड से जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करने और किशोर के संबंध में ऐसा आदेश देने की आवश्यकता थी जो वह उचित समझे। यदि किशोर न्याय बोर्ड को पता चलता है कि किशोर ने अपराध किया है तो जेजे अधिनियम की धारा 15 लागू हो जाती है। जेजे अधिनियम की धारा 15 के तहत, किशोर न्याय बोर्ड विभिन्न कदम उठा सकता था जैसा कि उसके तहत विचार किया गया था और उप-धारा (1) (जी) के तहत किशोर को 3 साल की अवधि के लिए एक विशेष गृह में भेजने का निर्देश

देने का आदेश देने का विवेकाधिकार था, जिसे परंतुक के संदर्भ में एक उपयुक्त मामले में कम किया जा सकता था।

22. इस न्यायालय के दिनांक 21.09.2012 के आदेश के अनुसार, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने जांच की और उसके बाद 28.11.2013 पर एक आदेश पारित किया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि अपीलार्थी संख्या 3 ने वर्ष 1981 में सेवा निकेतन हाई स्कूल, बरहुली, (कैमूर) से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और मैट्रिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि का उल्लेख 24.12.1965 के रूप में किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के सचिव ने यह भी कहा कि अपीलार्थी संख्या 3 वर्ष 1981 में मैट्रिक परीक्षा में उपस्थित हुआ था। स्कूल रजिस्टर के अनुसार, अपीलार्थी संख्या 3 की जन्म तिथि 24.12.1965 है। सी.बी.आई. ने यह भी पुष्टि की कि अपीलार्थी संख्या 3 की जन्म तिथि 24.12.1965 है। मामले के उस दृष्टिकोण में, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपराध की तारीख को अपीलार्थी संख्या 3 को किशोर घोषित कर दिया। विद्वान विशेष न्यायाधीश के दिनांकित 28.11.2013 आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> 18. इस प्रकार मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि दोषी बालमुकुंद जयसवाल तत्काल मामले से संबंधित अपराध की तारीख पर किशोर था।
>
> 19. परिणामस्वरूप दोषी बालमुकुंद जयसवाल को अधिनियम की धारा 7 और 49 के प्रावधानों के तहत किशोर घोषित कर दिया जाता है।

23. इसलिए, अब यह स्थापित हो गया है कि अपीलार्थी संख्या 3 अपराध करने की तारीख यानी सितंबर, 1982 से दिसंबर, 1982 तक की अवधि में एक किशोर था। उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा 29.05.2006 के फैसले और आदेश के माध्यम से दोषी

ठहराया गया था। आम तौर पर एक बार जब कोई अभियुक्त व्यक्ति अपराध करने की तारीख को किशोर पाया जाता है, तो उसे जेजे अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में आवश्यक जांच करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निपटा जाना आवश्यक था और उसके बाद धारा 15 के तहत आदेश पारित करना आवश्यक था, जिसमें किशोर को 3 साल की अवधि के लिए एक विशेष गृह में भेजने का आदेश भी शामिल था। तत्काल मामले में, अपराध को चार दशक से अधिक समय बीत चुका है। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी संख्या 3 के मामले को जेजे अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत अभ्यास करने के लिए संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को भेजना न तो संभव है और न ही व्यवहार्य। इसलिए, दिनांक 29.05.2006 के ट्रायल कोर्ट के निर्णय और आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2011 के निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता संख्या 3 के संबंध में पुष्टि की गई थी, को किशोर होने के आधार पर रद्द किया जाता है।

24. आइए अब हम अन्य दो अपीलार्थियों के मामले पर विचार करें।

25. जहाँ तक उक्त अपीलार्थियों का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने अ.सा.-3 रामेश्वर लाल शर्मा और अ.सा.-25 वेद कुमार के साक्ष्य के माध्यम से अपने अपराध को स्थापित करने का प्रयास किया। अ.सा.-3 ने कहा कि उन्होंने मेसर्स रोहतास कैरियर्स की शुरुआत की थी जिसमें रामजी प्रसाद जयसवाल भागीदारों में से एक थे। 28.11.1979 पर, रामजी प्रसाद जैसवाल ने साझेदारी छोड़ दी। तब से, मेसर्स रोहतास कैरियर्स अकेले अ.सा.-3 की स्वामित्व कंपनी बन गई। इस गवाह ने कहा कि 1979 के बाद उनकी कंपनी पटना में स्थानांतरित हो गई। इसके बाद मेसर्स रोहतास कैरियर्स का मोहनिया में कोई कार्यालय या व्यवसाय नहीं था।

26. अ.सा.-25 ने अपने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने वर्ष 1978 में एक व्यावसायिक कार्यकारी के रूप में मेसर्स रोहतास कैरियर्स की सेवा की थी। मेसर्स रोहतास कैरियर्स के मालिक रामेश्वर लाल शर्मा थे। इस फर्म की स्थापना 1975-1976 में की गई थी। उन्होंने पदच्युत किया कि रामजी प्रसाद जयसवाल पहले मेसर्स रोहतास कैरियर्स के भागीदारों में से एक थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 1979 में इसे छोड़ दिया था। तब से, साझेदारी फर्म को एक स्वामित्व वाली संस्था में बदल दिया गया, जिसने अपना कार्यालय और व्यवसाय पटना में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद मोहनिया में कोई रोहतास कैरियर्स अस्तित्व में नहीं था।

27. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने रामजी प्रसाद जयसवाल द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फ्रेजर रोड, पटना के शाखा प्रबंधक को लिखे गए एक पत्र (प्रदर्श 5) को भी प्रदर्शित किया। इस पत्र के अनुसार, रामजी प्रसाद जयसवाल ने रोहतास कैरियर्स से साझेदारी के अपने पूरे हिस्से ले लिए थे और उसके बाद उनका रोहतास कैरियर्स से कोई संबंध नहीं था। रामजी प्रसाद जैसवाल द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र से पता चलता है कि रामजी प्रसाद जैसवाल ने रोहतास कैरियर्स को 28.11.1979 पर छोड़ दिया था।

28. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, अपीलार्थियों सहित अभियुक्त व्यक्तियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, तीनों अपीलार्थियों से उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई विशिष्ट सामग्री पर ध्यान दिए बिना चार समान प्रश्न पूछे गए थे। अपीलार्थी नं. 1 से पूछे गए चार समान प्रश्न इस प्रकार थेः

    1. क्या आपने गवाहों के बयान सुने हैं?

    2. यह सबूत में आया है कि अगस्त से दिसंबर, 1982 की अवधि के दौरान मेसर्स बंसल स्टोर, मोहनिया और विष्णुजी भंडार, मोहनिया के

नाम पर 14 खेप नोट/परिवहन रसीदें संख्या 616, 617, 140 से 148, 1101, 1102, 625, 635 और 1104 तैयार की गई थीं?

3. यह भी सबूत में आया है कि आपने आरोपी अजय कुमार श्रीवास्तव, शिव नारायण बंसल, चैथख सिंह, बाल मुकुंद जैसवाल और अशोक कुमार जैसवाल के साथ मिलकर एक विशेष षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए जाली और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के साथ लेनदेन किया और 71,456.00 रुपये जमा करने के बाद, आपने बैंक को 12,57,810.00 रुपये की धोखाधड़ी की?

4. क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?

29. द.प्र.स की धारा 313 अभियुक्त की जाँच करने की अदालत की शक्ति से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 इस प्रकार हैः

313. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। --(1) प्रत्येक जांच या विचारण में, अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय--

(ए) अभियुक्त किसी भी स्तर पर, पूर्व में चेतावनी दिए बिना, उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे;

(बी) अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ किए जाने के बाद और अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, मामले पर आम तौर पर उससे पूछताछ करेगाः

बशर्ते कि समन-मामले में, जहां अदालत ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया है, वह खंड (बी) के तहत उसकी परीक्षा को भी समाप्त कर सकती है।

(2) जब अभियुक्त से उप-धारा (1) के तहत पूछताछ की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करके या उन्हें गलत उत्तर देकर खुद को दंडनीय नहीं ठहराएगा।

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है, और किसी अन्य अपराध की जांच या मुकदमे में उसके पक्ष या उसके खिलाफ साक्ष्य दिया जा सकता है, जो इस तरह के उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है।

(5) न्यायालय प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की मदद ले सकता है जिन्हें अभियुक्त के समक्ष रखा जाना है और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।

30. *शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य*[1] में, यह न्यायालय पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 की जांच कर रहा था, जो द.प्र.स की धारा 313 के समरूप है और उसने ऐसे प्रावधान के पीछे के औचित्य को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

16..... हालाँकि, यह मौलिक कानून है कि कैदी का ध्यान प्रत्येक उपदेशात्मक सामग्री की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि वह इसे समझाने में सक्षम हो सके। यह आपराधिक मुकदमे की बुनियादी निष्पक्षता है और इस क्षेत्र में विफलताएं मुकदमे की वैधता को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती हैं, अगर परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। हालांकि, जहां ऐसी

[1] (1973) 2 एससीसी 793

चूक हुई है, वह वास्तव में कार्यवाही को दूषित नहीं करती है और इस तरह के दोष के कारण होने वाले पूर्वाग्रह को अभियुक्त द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। अभियुक्त के सामने साक्ष्य सामग्री नहीं रखे जाने की स्थिति में, अदालत को आम तौर पर ऐसी सामग्री पर विचार करने से बचना चाहिए। अपीलीय न्यायालय के लिए यह भी खुला है कि वह अभियुक्त के वकील से यह दिखाने के लिए कहे कि अभियुक्त के पास उसके खिलाफ स्थापित परिस्थितियों के संबंध में क्या स्पष्टीकरण है, लेकिन उसे नहीं दिया गया है और यदि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों का कोई प्रशंसनीय या उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि कोई स्वीकार्य उत्तर मौजूद नहीं है और भले ही अभियुक्त से विचारण न्यायालय में उचित समय पर पूछताछ की गई हो, वह उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए कोई अच्छा आधार प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होता, जिन पर विचारण न्यायालय ने अपनी दोषसिद्धि के लिए भरोसा किया था। ऐसे मामले में, अदालत इस आधार पर आगे बढ़ती है कि हालांकि धारा 342, द.प्र.स के अनुपालन के संबंध में एक गंभीर अनियमितता हुई है, लेकिन यह नहीं दिखाया गया है कि चूक ने आरोपी के लिए पूर्वाग्रह पैदा किया है।

31. धारा 313 द.प्र.स., *धारनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*[2] में विचार के लिए आई जहां इस न्यायालय ने धारा 313 द.प्र.स के तहत एक आरोपी का बयान दर्ज करते समय अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली उचित कार्यप्रणाली को रेखांकित किया। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

---

[2] (2010) 7 एससीसी 759

29. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करते समय अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली उचित कार्यप्रणाली अभियुक्त का ध्यान उस अपराध के संबंध में परिस्थितियों और पर्याप्त साक्ष्य की ओर आकर्षित करना है, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है और उसका स्पष्टीकरण आमंत्रित करना है। दूसरे शब्दों में, यह एक अभियुक्त को अदालत के समक्ष यह बताने का अवसर प्रदान करता है कि कानून के अनुसार सच्चाई क्या है और उसका बचाव क्या है। यह अभियुक्त पर था कि वह उस अवसर का लाभ उठाए और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो यह अदालत पर है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में अपने साक्ष्य पर अभियोजन पक्ष के मामले की जांच करे।

32. इस न्यायालय ने *राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बट्या बनाम राजस्थान राज्य*[3] मामले में धारा 313 द.प्र.स के तहत एक अभियुक्त का बयान दर्ज करने के उद्देश्य पर चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय दिया:

30. आपराधिक मुकदमे में, धारा 313 द.प्र.स के तहत आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करने का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों यानी ऑडी अल्टरम पार्टेम की आवश्यकता को पूरा करना है। इसका मतलब है कि अभियुक्त को उससे जुड़ी आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जा सकता है, और अदालत को इस तरह के स्पष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, यह तय करने के लिए भी यही आवश्यक है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हुई है या नहीं। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त से पूछताछ करे और उसके खिलाफ सामने आई

[3] (2013) 5 एससीसी 722

आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में उसका स्पष्टीकरण मांगे। द.प्र.स की धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच में जिन परिस्थितियों को नहीं रखा गया है, उनका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है और उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

33. पुनः, *राज कुमार उर्फ सुमन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)*[4] में, इस न्यायालय ने धारा 313 द.प्र.स के संबंध में कानून का सारांश इस प्रकार दिया:

> 22. इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः
>
> 22.1. विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से और अलग से रखे। भौतिक परिस्थिति का अर्थ है वह परिस्थिति या सामग्री जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी दोषसिद्धि की मांग कर रहा है।
>
> 22.2. धारा 313 के तहत अभियुक्त से पूछताछ का उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है।
>
> 22.3. न्यायालय को आम तौर पर उन भौतिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जो विशेष अभियुक्त के मामले पर विचार करते समय अभियुक्त को विचार से नहीं रोकती हैं।

---

[4] (2023) 17 एससीसी 95

22.4. अभियुक्त के सामने भौतिक परिस्थितियों को रखने में विफलता एक गंभीर अनियमितता है। यह मुकदमे को दूषित कर देगा यदि यह दिखाया जाता है कि इसने आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह दिखाया है।

22.5. यदि अभियुक्त के सामने भौतिक परिस्थिति रखने में किसी भी अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है, तो यह एक उपचार योग्य दोष बन जाता है। हालांकि, यह तय करते समय कि क्या दोष को ठीक किया जा सकता है, एक विचार घटना की तारीख से समय के बीतने पर होगा।

22.6. यदि ऐसी अनियमितता ठीक की जा सकती है, तो अपीलीय न्यायालय भी अभियुक्त से उस भौतिक परिस्थिति पर सवाल कर सकता है जो उसके सामने नहीं रखी गई है।

22.7. किसी मामले में, मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत संबंधित आरोपी का पूरक बयान दर्ज करने के चरण से विचारण न्यायालय में भेजा जा सकता है।

22.8. इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि क्या चूक के कारण अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, विवाद उठाने में देरी उन कई कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

34. हाल के एक निर्णय में, *अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*[5] में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

23. वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली भौतिक परिस्थितियों को उसके सामने नहीं रखा

[5] (2025) 2 एससीसी 381

गया है। मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाह अ.सा. 1 और 2 का बयान उनके सामने नहीं रखा गया था। अभियुक्त द्वारा बचाव पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व करने का चरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसका बयान दर्ज होने के बाद ही उत्पन्न होता है। जब तक उसके खिलाफ साक्ष्य में पेश होने वाली सभी भौतिक परिस्थितियों को अभियुक्त के सामने नहीं रखा जाता है, तब तक वह यह तय नहीं कर सकता कि वह कोई बचाव साक्ष्य पेश करना चाहता है या नहीं।

24. इस मामले में, अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की तारीख और स्थान भी अपीलार्थी के सामने नहीं रखा गया था। अ.सा.-2 द्वारा कथित तौर पर जो देखा गया था, उसे अपीलार्थी की जाँच में नहीं रखा गया था। इसलिए, अपीलार्थी पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी की जाँच में सामग्री रखने में विफलता एक अनियमितता है, सवाल यह है कि क्या मामले को विचारण न्यायालय में भेजकर इसे ठीक किया जा सकता है।

35. इस प्रिंट पर कानून का सर्वेक्षण करने के बाद, आइए हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटें। जिस तरह से विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए थे, वह उक्त प्रावधान की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था, जैसा कि इस अदालत ने ऊपर चर्चा की थी।

36. आम तौर पर अपीलार्थियों से चार प्रश्न पूछे गए थे, वह भी बहुत ही यांत्रिक तरीके से। ये प्रश्न अभियोजन पक्ष के विशिष्ट साक्ष्य को प्रतिबिंबित नहीं करते थे जो अपीलार्थियों के रिकॉर्ड में आए थे। चूंकि सभी दोषपूर्ण साक्ष्य अपीलार्थियों के ध्यान में नहीं रखे गए थे, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के साथ-साथ *ऑडी अल्टरम पार्टेम* के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन किया गया था। निश्चित रूप से, इसने

अपीलार्थियों को अपना मामला रखने के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया। अंततः, अदालत ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने के लिए ऐसे सबूतों पर भरोसा किया।

37. इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की चूक, जो एक गंभीर अनियमितता है, ने मुकदमे को पूरी तरह से दूषित कर दिया है। भले ही हम यह विचार रखते हुए अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं कि इस तरह की चूक के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं हुई है, फिर भी यह एक भौतिक दोष है, हालांकि इसका इलाज किया जा सकता है। *राज कुमार (ऊपर)* में, इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के दोष को ठीक किया जा सकता है या नहीं, यह तय करते समय, घटना की तारीख से समय बीतने पर विचार किया जाएगा।

38. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, जिस अवधि के दौरान अपराध कथित रूप से किया गया था, वह सितंबर, 1982 से दिसंबर, 1982 तक था। परीक्षण 29.05.2006 पर समाप्त हुआ। तब से उन्नीस साल बीत चुके हैं। इस दूर के समय में, न्याय के कारण में सहायता करने के बजाय, यह न्याय की विफलता का कारण बन जाएगा यदि मामले में दोनों अपीलार्थियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के चरण से मुकदमे को फिर से शुरू करने के लिए विचारण न्यायालय में भेज दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि इस तरह की रिमांड का आदेश देना न तो संभव है और न ही व्यवहार्य है। नतीजतन, अपीलार्थी धारा 313 द.प्र.स के तहत अपने बयानों की रिकॉर्डिंग में इस तरह की चूक के कारण संदेह के लाभ के हकदार हैं क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराते समय उनके प्रतिकूल साक्ष्य पर भरोसा किया था।

39. इसलिए, उनकी दोषसिद्धि और सजा असमर्थनीय हो गई है। नतीजतन, हम विचारण न्यायालय के दिनांकित 29.05.2006 और उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.11.2011 के फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

40. चूंकि अपीलार्थी जमानत पर हैं, इसलिए उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं।

41. तदनुसार आपराधिक अपील की अनुमति दी जाती है।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

† द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः दिव्या पांडे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।